MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

No. 11(5)/2009-DBA-II/NER.—The Government of India hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 11(5)/2009-DBA-II/NER dated the 22nd January, 2013 called the Freight Subsidy Scheme, 2013.

2. In place of existing clause 10(2) of Government of India Notification No. 11(5)/2009-DBA-II/NER dated the 22nd January, 2013, the following shall be substituted:

10. Role and functions of the State Government/Union Territory Administration under the scheme—

(2) The State Govt./Union Territory Administration concerned shall set up a State Level Committee (SLC), consisting of the Principal Secretary/Secretary(Industry Department of the State Govt./Union Territory concerned), Director of Industries of the State/ Union Territory concerned and a representative each from the Finance Department of the State/Union Territory concerned, Excise and Taxation Department of the State/Union Territory concerned (Excise Commissioner), Transport Department of the State/ Union Territory concerned, nodal agency concerned and Department of Industrial Policy & Promotion, GOI to consider and recommend all subsidy claims, under the scheme, arising in the State/Union Territory.

RAVNEET KAUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937
No. 78] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

सं. 11 (5)/2009-टीडीए-II/एनईआर.—भारत सरकार एतद्द्वारा मालभाड़ा राजसहायता स्कीम, 2013 नामक भारत सरकार की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-टीडीए-II/एनईआर दिनांक 22 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. भारत सरकार की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-टीडीए-II/एनईआर दिनांक 22 जनवरी, 2013 के मौजूदा खण्ड 10(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. **इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/संघीय प्रदेश प्रशासन की भूमिका तथा कार्य-**

(2) योजना के तहत राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र में प्राप्त सभी राजसहायता दावों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करेंगे, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव (संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग विभाग, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशक तथा संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित क्षेत्र के वित्त विभाग, संबंधित राज्य/संघीय प्रदेश के उत्पाद शुल्क तथा कराधान विभाग (उत्पाद आयुक्त), संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के परिवहन विभाग, संबंधित नोडल एजेंसी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव